

साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और माफिया गैंग

जहां युवा बेरोजगारी असामान्य रूप से ऊंची हो और खाद्य मुद्रास्फीति लगातार आठ प्रतिशत से ऊपर हो, वहां कैसी जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? अप्रैल के जारी ताजा आंकड़ों में भी खाद्य मुद्रास्फीति 8.7 प्रतिशत दर्ज हुई है कुवैत में विदेशी मजदूरों के एक रहवास में हुए भयंकर अग्निकांड में मरे 49 लोगों में तकरीबन 40 भारतीय हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भाड़े के सैनिक के तौर पर गए दो और भारतीयों की मौत हो गई है। ये भारतीय उन 30 लोगों से अलग हैं, जिनके परिजनों ने भारत सरकार से संपर्क किया था। मतलब यह कि रूस की तरफ से लड़े के लिए जिन भारतीयों को बहला-फुसलां करने के लिए जाए तो मन में पहली नजर में भाव यह उभरता है कि त्रासदी कहीं हो। उससे भारतीयों का कोई ना कोई संबंध निकल आता है। अखिर देश में अवसरों की इतनी कमी और उससे उत्पन्न निराशा इतनी व्यापक क्यों है कि देशवासी कहीं भी जाकर अपनी जन खतरे में डालने के लिए नियर हो जाते हैं? हम कुछ आंकड़ों पर गर करें, तो इस बारे में कुछ सकें तथा सकते हैं। मसलन, जहां युवा बेरोजगारी असामान्य रूप से ऊंची हो और खाद्य मुद्रास्फीति लगातार आठ प्रतिशत से ऊपर चल रही हो, वहां आम जन की कैसी जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? अप्रैल के जारी ताजा आंकड़ों में भी खाद्य मुद्रास्फीति 8.7 प्रतिशत दर्ज हुई है कुल आलाम यह है कि सर्वे एजेंसी गैलेप के एक विश्वव्यापी अकलन में सामने आया कि भारत में सिर्फ 14 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी स्थिति को खुशहाल श्रेणी में रखा। बाकी 86 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी हालत को संघर्षत या पोटायाक बताया। जबकि अपने के खुशहाल बताने वाले कर्मचारियों का वैश्वक औसत 34 प्रतिशत था। असामक तबकों और उनके संचार माध्यमों की तरफ से इस जमीनी सूत्र पर परदा डालने के सुनियोजित अभियान लगातार चलाए जाते हैं। मगर उनसे संकट अब छिपाये नहीं छिप रहा है। अब हाल यह है कि अक्सर बुनावों के बाद दिखने वाला आशावाद भी इस बार गायब ही रहा है।



डा. सत्यवान सारम् लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

S

कल क द्वाया साहित्य अकादमी द्वारा 2024 के युवा व बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की सोशल मीडिया पर खबर के बाद बधाईयों के साथ-साथ, जैसे अकादमी पुरस्कारों की लेकर हर साल होता रहा है, कोई न कोई सवाल, विवाद तो उठता ही उठता है, इस बार भी कुमार सुशांत ने प्रविष्टि की अंतिम तिथि, और उसके बाद छपी पुस्तकों पर सवाल उठाते अनुमानित कर।

नियम 7-विविध के पहले पैराग्राफ में यह जरूर लिखा है कि यदि भाषा परमार्थ मण्डल के किसी सदस्य या निर्णायक के द्वारा संस्तुति भेजने की समय सीमा की अनदेखी या जाती है तो अकादमी यह मानकर चलेगी कि उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार प्रक्रिया को आग बढ़ाएगी सिवाय उस विशेष रकमण्डल नाम पर हा कवाल विचार में यह जरूर लिखा है कि यदि भाषा परमार्थ मण्डल के किसी सदस्य या उनकी पुस्तक पर (रिमेंड न होने के कारण) विचार ही नहीं किया गया। लिस्ट में शामिल किस किताब को किस ज्यूरी में रेकॉर्ड किया गया साहित्य अकादमी यह बतलायेगी?

प्रसिद्ध आलोचक, कवि, लेखक नवनीत पांडेय के अनुसार सवाल यह

नियमिक मण्डल, पनल तात्त्व के बाद प्राप्त, प्रकाशित किताबों पर विचार कर उसे अंतिम सूची में शामिल कर उन्हें पुरस्कार योग्य पाती है, पुरस्कार घोषित करती है तो अवश्य ही ये प्रतिभाएँ अप्रतिम और विलक्षण हैं, इस में सदैह नहीं होना चाहिए।

यदि दिला दूँ कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार-2024 हेतु आवेदन और प्रविष्टि जमा करने की अंतिम

पाठक दिना पुस्तकों के प्रकाशन का प्रमाण गूगल में देखें। ऐसी स्थिति में साहित्य अकादमी ने इन दोनों लेखकों की पुस्तकों पर विचार कैसे किया? इन दोनों पुस्तकों का नाम अंतिम सूची में कैसे है? नियमतः तो यह अमान्य और अनैतिक है। इस विषय पर शोध करने के दौरान पाया कि पुरस्कृत लेखक की पुस्तक 30 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुई और 31 अगस्त 2023 तक दिला दूँ कि साहित्य अकादमी की पोल खोली है जाए। यह अन्य समय युवा लेखकों के साथ ज्यादात है। यह तो बहुत गंभीर बाली है, पारदर्शिता का दावा करने वाली अकादमी को लिए बहुत सज्जन लेना चाहिए, अकादमी सचिव, अध्यक्ष से जवाब तलब करना चाहिए। सुशांत जी, आपने प्रमाण सहित जो साहित्य अकादमी की पोल खोली है उस पर सभी साहित्यकारों की हाइ-

पिंड आवासों के साथ काम की गति का राजा

इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कटुआ और डोडा में चार दिनों में चार आतंकी हमले चिन्हां का बड़ा कारण बने हैं। रविवार को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस के चालक पर हुए हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। जिसमें नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फिर कटुआ व डोडा में हुए आतंकी हमलों में एक जवान और दो आतंकवादी मारे गए हैं। लम्बे समय की शांति, अमन-चैन एवं खुशहाली के बाद एक बार फिर कश्मीर में अशांति एवं आतंक के बादल मंडराये हैं। धररी के स्वर्ण की आभा पर लगे ग्रहण के बादल छंटने लगे थे कि एक बार फिर कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें तीव्र होते हुए दिख रही हैं। केन्द्र में गढ़बंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। इन आतंकी घटनाओं को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं और हथियार भी बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की है। इसमें आतंकवाद की नई चुनौती से मुकाबल की रणनीति पर विचार हुआ है। दरअसल, नई सरकार बनने की प्रक्रिया के दौरान हुए इन हमलों में पाक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान यह बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की दृष्टा एवं साहस को चुनौती देना इतना आसान नहीं है।



लालत गग लेखक शिक्षाविद है

୪

भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी एवं पाकिस्तान पोषित आतंकवाद फिर से फन उठाने लगेगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमले। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कटुआ और डोडा में चार दिनों में चार आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने हैं। रविवार को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस के चालक पर हुए हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खार्ड में गिर गई थी। जिसमें नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फिर कटुआ व डोडा में हुए आतंकी हमलों में एक जवान और दो आतंकवादी मारे गए हैं। लम्बे समय की शांति, अमन-चैन एवं खुशहाली के बाद एक बार फिर कश्मीर में अशांत एवं आतंक के बादल मंडराये हैं। धरती के स्वर्ग की आभा पर लगे ग्रहण के बादल छंटने लगे थे कि एक बार फिर कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें तीव्र होते हुए दिख रही हैं। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है।

सरकार ने गंभीरता से लिया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और हथियार भी बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की है। इसमें आतंकवाद की नई चुनौती से मुकाबले की रणनीति पर विचार हुआ है। दरअसल, नई सरकार बनने की प्रक्रिया के दौरान हुए इन हमलों में पाक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान यह बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की दृष्टि एवं साहस को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। फिर भी लगातार हुए आतंकी हमले चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं। एलओसी से लगते जम्मू के इलाके में आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना गंभीर है, चिन्ताजनक है। मारे गये दो आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी हथियार व सामान की बरामदगी बताती है कि पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांत एवं अमन को पूर्व अपनी एक सप्ताह की कश्मीर यात्रा में देखा कि केन्द्र सरकार ने कश्मीर मी विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही हैं, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीरी देश के माये का ऐसा मुकूट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उस डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। लेकिन वहां विकास एवं शांति स्थापना का ही परिणाम रहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया। कहा जा सकता है कि राज्य में लोकतंत्र को मजबूत होते देख बौखलाहट में ये आतंकवादी हमले किये जा रहे हैं। दरअसल, केंद्रसांसित प्रदेश का शांति-सुरक्षन की तरफ बढ़ना आतंकवादियों को हताशा को ही बढ़ाता है। हाल के दिनों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का घाटी में आना और लोकसभा चुनाव में बंपर मतदान सीम पर बैठे आतंकियों के आकाओं को रास नहीं आया है।

में वृद्धि शासन-प्रशासन के लिये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि रविवार को हुए हमले की जिम्मेदारी जहां लशकर-ए-तैयबा के आतंकी गृह टीराएर ने ली तो डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी पाक पोषित जैश-ए-मोहम्मद के एक गुट कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन ने ली है। बहरहाल, भारतीय सेना व सुरक्षा बल आतंकवादियों को भरपूर जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस माह के अंत में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का निर्बाध आयोजन सुरक्षा बलों के लिये बड़ी चुनौती होगी। जिसके लेकर विशेष चौकसी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर हाल के आतंकी हमले में अपना विश्वास व्यक्त किया। कहा जा सकता है कि राज्य में लोकतंत्र की अधिकारों की सुरक्षा व संपत्ति के अधिकारों को लेकर मन में संशय की स्थिति में वृद्धि हुई है? हमें यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि किसी भी राज्य में आतंकवाद का उभरना स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। वहीं यह भी हकीकत है कि कश्मीरी जनमानस का दिल जीतना शक्ति से नहीं बल्कि उनके अनुकूल नीतियां बनाने व लोकतंत्र की बहाली से ही संभव है। अब कश्मीर में आतंक का अंधेरा नहीं, शांति का को सशक्त बनाने का, विकास के कार्यक्रमों को गति देने का एवं कश्मीर के लोगों पर आयी मुस्कान को कायम रखने का। बेशक यह कठिन और पेचीदा काम है लेकिन राष्ट्रीय एकता और निर्माण संबंधी कौन-सा कार्य पेचीदा और कठिन नहीं रहा है? इन कठिन एवं पेचीदा कामों को आसान करना ही तो नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार का जादू रहा है। अब गठबंधन सरकार में भी वे अपने इस जादू को दिखाये। इन आतंकी हमलों ने अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कश्मीर की जनता क्यों राष्ट्रीय की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पा रही है? क्या कश्मीरी लोगों में नई व्यवस्था में अपने अधिकारों की सुरक्षा व संपत्ति के अधिकारों को लेकर मन में संशय की स्थिति में वृद्धि हुई है? हमें यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि किसी भी राज्य में आतंकवाद का उभरना स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। वहीं यह भी हकीकत है कि कश्मीरी जनमानस का दिल जीतना शक्ति से नहीं बल्कि उनके अनुकूल नीतियां बनाने व लोकतंत्र की बहाली से ही संभव है। अब कश्मीर में आतंक का अंधेरा नहीं, शांति का भय का माहौल ही बनाती है। माना कि रोग पुराना है, लेकिन ठोस प्रयासों के जरिए इसकी जड़ का इलाज होना ही चाहिए। कश्मीरियों में अपनी सुरक्षा के प्रति भरोसा जगाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। घाटी में सक्रिय आतंकियों के खात्मे में सुरक्षा तंत्र ने काफी कामयाचियां हासिल की हैं। अब जरूरत है खुफिया तंत्र को दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करने को तैयार एवं सक्षम किया जाये। घाटी में हालात सुधरने के केंद्र सरकार के दावों की सत्यता इसी से परखी जाएगी कि घाटी में अल्पसंख्यक पड़ित और प्रवासी कामगार खुद को गिरावट ने सुरक्षित महसूस करते हैं। वास्तव में देखा जाये तो असली लड़ाई कश्मीर में बन्दूक और सन्दूक की है, आतंकवाद और लोकतंत्र की है, अलगाववाद और एकता की है, पाकिस्तान और भारत की है। शांति का अग्रदूत बन रहा भारत एक बार फिर युद्ध के जंग की बजाय शांति प्रयासों एवं कूटनीति से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाये, यह अपेक्षित है। पाकिस्तान एक दिन भी चुप नहीं बैठा, लगातार आतंक की आंधी को पोषित करता रहा, अपनी इन कुचेष्ठाओं के चलते वह कंगाल हो चुका है,

संपन्न की है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात नहीं होती है। यह दोनों देशों का सर्वकालिक समर्थक रहा है। रूस-युक्रेन युद्ध में भारत की तरफ से लगातार जिहाद का खुलकर विरोध किया है। पहले का इंतजार कर रहा है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में प्रयासों तथा शांति निवहन सक्रियाओं का समर्थन कर रचनात्मक सहयोग का दर्शाव किया है।

प्रधानमंत्री १
बार भारत के

पांचवीं बार जी-7 सेवन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर यह बैठक वैश्विक परिवृश्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैन्को एवं इटली की राष्ट्रपति प्रमुख मेलेनी तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की से अलग-अलग मुद्रों पर द्विपक्षी बैठक प्रयास भी हुए हैं। यह अलग बात है कि विस्तारवादी दृष्टिकोण को लेकर पुतिन और जेलेन्स्की अजीब सी राजनीतिक और कृतनीतिक परिस्थितियों में एक-दूसरे के सामने खड़े तथा अड़े हैं। अब इस्राइल-हमास युद्ध में भारत की नीति स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद के विरोध में रही है। भारत हमेशा से शांति सद्व्यवहार और सौहार्द भारत ने आतंकवादी संगठन हमास, प्रयास भी हुए हैं। यह अलग बात है कि विस्तारवादी दृष्टिकोण को लेकर पुतिन और जेलेन्स्की अजीब सी राजनीतिक और कृतनीतिक परिस्थितियों में एक-दूसरे के सामने खड़े तथा अड़े हैं। अब इस्राइल-हमास युद्ध में भारत की नीति स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद के विरोध में रही है। भारत हमेशा से शांति सद्व्यवहार और सौहार्द भारत ने आतंकवादी संगठन हमास, लिए सैकड़ा टन खाद्य सामग्री दिवाएं और आवश्यक वस्तुएं तत्काल मुहैया कराई है।

भारत के संबंध रूस के साथ-साथ जी-7 के सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जापान, कनाडा और नारो देशों से भी मधुर हैं। इन परिस्थितियों में अरब देश भारत के प्रति युद्ध विराम की संभावनाओं की तलाश में भारतीय वियतनाम, लागोस, मिस्र, सीरिया, लाइबेरिया, युगोस्लाविया, नार्मीबिया, सोमालिया, सूडान सहित अनिनगत देशों में अपनी सेनाएं वहां पर शांति बहाली के लिए अलग-अलग समय में उपलब्ध करवाई थी। भारत द्वारा विश्व शांति की स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों में अनश्वक एवं बहुत बड़ा रहा है।

